दोपहिया पर हेलमेट नहीं तो सफर नहीं

यातायात पुलिस ने छात्र-छात्राओं को दी सड़क सुरक्षा की जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली अकाल मौतों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को पन्ना पुलिस ने स्थानीय शुक्ला एवं खरे कोचिंग सेंटर पहुंचकर छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक नीलम लक्षकार ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहन पर चालक के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी आईएसआई मार्क वाला हेलमेट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेलमेट केवल सिर पर रखना काफी नहीं है, बल्कि उसकी बेल्ट को सही तरीके से बांधना ही जीवन की रक्षा सुनिश्चित करता है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन में चल रहे इस 15 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान पुलिस अब शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच रही है। जागरूकता कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 50 प्रतिशत मामले दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं, जिनमें अधिकांश की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता।

बंदिश नहीं आपका सुरक्षा कवच

युवाओं को सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाते हुए कहा कि यातायात नियम आपकी बंदिश के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में बनाए गए हैं। निरीक्षक नीलम लक्षकार ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे न केवल स्वयं नियमों का पालन करें, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रति सचेत करें। पुलिस ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी स्पष्ट किया कि 26 अप्रैल से 10 मई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चार पहिया वाहन चलाने वालों के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है कि चालक सहित उसमें सवार सभी यात्री सीट बेल्ट का उपयोग करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तारा में वन विभाग के अधिकारियों को बंधक बनाने का प्रयास करने और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई।

घटना बीते 26 अप्रैल की है, जब ग्राम तारा में एक टाइगर द्वारा मवेशी का शिकार किए जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाने और भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने परिक्षेत्र अधिकारी को बंधक बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता और धमकी देते हुए सरकारी काम में व्यवधान पैदा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अमानगंज में फरियादी की शिकायत पर विभिन्न बीएनएस धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद अमानगंज थाना प्रभारी उप निरीक्षक रवि सिंह जादौन की एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और सूचना के आधार पर दबिश देकर दो संदेही व्यक्तियों, कुन्जीलाल कुशवाहा और रामरूप कुशवाहा को हिरासत में लिया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

बाइक चोरी के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता नायडू के निर्देशन में अमानगंज थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक चोरी के एक मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है।

पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार, सिरसी पटना निवासी संजय कुमार दीक्षित बीते रविवार को अमानगंज में कूलर खरीदने आए थे। उन्होंने अपनी एचएफ डीलक्स बाइक रानू पाठक की मोबाइल दुकान के सामने खड़ी की थी, जिसे कोई अज्ञात चोर पार कर ले गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना पर थाना प्रभारी रवि सिंह जादौन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर संदेही धरमू चौधरी को हिरासत में लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और छिपाकर रखी गई बाइक बरामद करवा दी। गिरफ्तार आरोपी वार्ड नंबर 06, रेस्ट हाउस मोहल्ला अमानगंज का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

शहर में नहीं पार्किंग, दुकानदार एवं ग्राहक दोनों परेशान

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। करीब 80 हजार लोगों की आबादी वाले पन्ना शहर के मार्केट में एक भी वाहन पार्किंग नहीं है। दुकानों के सामने वाहनों को पार्क कर खरीदारी करने से जाम के हालात बनते हैं। इससे खरीदारी करने वाले और दुकानदार दोनों परेशान हो रहे हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है।

शहर के अंदर वाहन पार्किंग सुविधा विकसित करने की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन किसी ने भी अभी तक समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। पहले जुगल किशोरजी मंदिर से लगी रामलीला समिति की के भवन को तोड़कर पार्किंग विकसित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन यहां भगवान जुगल किशोर लोक विकसित करने की सीएम की घोषणा के बाद पार्किंग का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही शहर के लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। मार्केट का भी विकास हो रहा है। इस अनुपात में शहर की सड़कों को चौड़ा नहीं किया गया है। इसके साथ ही मार्केट में कहीं भी वाहन पार्किंग की सुविधा नहीं है। आलम यह है कि मार्केट में चार पहिया वाहन से खरीदारी करने के लिए जाने से लोग बचते हैं। जो लोग वाहन से मार्केट में आ जाते हैं, उन्हें कहीं वाहन खड़े करने की जगह ही नहीं मिलती। मजबूरी में जिस दुकान से सामग्री लेनी होती है, उसी के सामने सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं।

सड़कों पर ही वाहनों की रिपेयरिंग:-वाहनों की रिपेयरिंग का काम करने वाले मिस्त्री नाली पर दुकानें लगाते हैं और उसके बाद सड़क पर वाहन खड़ा करके उनकी रिपेयरिंग करते हैं। शहर के छत्रसाल कॉलेज के पास, पॉलीटेक्निक के आगे, एनएच-39 में डायमंड चौराहे के आगे चार पहिया वाहनों की रिपेयरिंग की जाती है। जबकि श्रीराज जानकी मंदिर के पास, गांधी चौक के पास, हाजी बिल्डिंग के पास बाइक रिपेयरिंग की दुकानें चल रही हैं।

सालों से की जा रही पार्किंग की मांग:- नगर के लोग और दुकानदार लंबे समय से मार्केट क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी सांसद से लेकर विधायक तक और नगर पालिका से लेकर यातायात पुलिस तक किसी ने भी सुगम यातायात के लिए वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाया है।

पूरे शहर में एक जैसे हालात

श्रीराम जानकी मंदिर से अजयगढ़ चौक, वहां से बड़ा बाजार, बड़ा बाजार से गोविंदजी मंदिर मार्ग, मनहर कन्या स्कूल के सामने, छत्रसाल कॉलेज के गेट के सामने, जिला अस्पताल परिसर, पॉलीटेक्निक कॉलेज के आगे, सहारा मार्केट के पास, आरपी रमांक-2 के पास, हाली बिल्डिंग के पास महेंद्र भवन के पीछे वाले गेट के पास अधिकांश जगहों पर स्थायी रूप से वाहन पार्क रहते हैं या फिर खरीदारों के वाहन खड़ा करने से दूसरे वाहनों के चालकों को आवागमन में परेशानी होती है।

जिगनी में पर्ची से फैसला राधा बनीं जिगनी सरपंच

पन्ना 29 अप्रेल। जनपद पंचायत अजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत जिगनी में रिक्त सरपंच पद के लिए आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में राधा लोध को सरपंच घोषित किया गया। चुनाव परिणाम बराबरी पर दोनों उम्मीदवारों को 7-7 वोट मिलने पर पर्ची निकालकर फैसला किया गया, जिसमें राधा लोध के नाम की पर्ची निकली। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जिगनी की पूर्व सरपंच रानी लोध का 19 मार्च को निधन हो गया था। इसके बाद सरपंच पद रिक्त हो गया था। रिक्त पद की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ ने नियमानुसार निर्वाचन कराने के निर्देश दिए थे। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दो महिला पंचों राधा लोध पति मूरत सिंह लोध तथा प्रेमा लोध ने नामांकन दाखिल किया। मतदान प्रक्रिया में पंचों ने भाग लिया। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशियों को समान रूप से सात-सात मत प्राप्त हुए। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों की सहमति से छोटी बच्ची के माध्यम से पर्ची निकलवाई गई। पर्ची में राधा लोध का नाम आने पर पीठासीन अधिकारी ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी शिव बिहारी तिवारी, पीसीओ अजयगढ़ के निर्देशन में पारदर्शी तरीके से कराई गई। नई सरपंच बनने पर समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।

ककरन तलैया के पास मिला 30 वर्षीय अनिल का शव

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। अमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्होरी में एक युवक की धारदार हथियार से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अनिल दहायत के रूप में हुई है, जिसका शव आज बुधवार 29 अप्रेल को ककरन तलैया के पास संदिग्ध अवस्था में मिला।

घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत के बाद उसकी दो मासूम बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के पिता बैजू दहायत ने गांव के ही चार व्यक्तियों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि उनका पुत्र मंगलवार शाम करीब 5 बजे घर से निकला था। जिसके बाद वह घर नही लौटा फिर आज उन्हें गाँव के लोगो ने जानकारी दी कि उनके बेटे का शव तलैया के पास पड़ा है।

पिता ने लगाया हत्या का आरोप

हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हत्या के असली कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा।

56 लाख की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा मामला

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जेके पिल्लई की एकलपीठ ने धान उपार्जन केंद्र रैगवां, जिला पन्ना के केंद्र प्रभारी व समिति प्रबंधक को बड़ी राहत दी है। इसके तहत 56 लाख की वसूली पर रोक लगा दी है।

साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना उचित सुनवाई और बिना यह बताए कि इतनी बड़ी राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया, किसी कर्मचारी पर सीधे नागरिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ता पन्ना निवासी बलराम उरमलिया की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पन्ना द्वारा जारी रिकवरी नोटिस चुनौती के योग्य है। इस नोटिस में 2375.04 क्विंटल धान की कमी बताते हुए 56 लाख 26 हजार 469 की राशि तीन दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा कठोर वसूली की चेतावनी दी गई थी। याचिकाकर्ता पिछले लगभग 20 वर्षों से सहकारी विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान धान उपार्जन केंद्र रैंगवां का अतिरिक्त प्रभार केंद्र प्रभारी के रूप में सौंपा गया था। उन्होंने शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान की खरीदी, इलेक्ट्रानिक तौल, ई-उपार्जन पोर्टल प्रविष्टि व परिवहनकर्ता को विधिवत सुपुर्दगी की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की थी।

गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन और प्रसव पूर्व जाँच अनिवार्य : परमार

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिला स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती उषा परमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्ष के लिए सख्त तेवर दिखाए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नए साल के पहले महीने से ही ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों को हासिल किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले की हर गर्भवती महिला का अनमोल पोर्टल पर समय पर पंजीयन सुनिश्चित हो। उन्होंने प्रथम तिमाही में पंजीयन और प्रसव पूर्व होने वाली चारों जाँचों को अनिवार्य बताया। साथ ही, जिले से बाहर जाने वाली गर्भवती महिलाओं का अलग से रिकॉर्ड संधारण करने के निर्देश दिए ताकि उनकी निगरानी की जा सके। एनीमिक माताओं को आयरन सुक्रोज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर पोर्टल पर रियल-टाइम एंट्री करने को कहा गया। संस्थागत प्रसव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को मैदानी स्तर पर संयुक्त रूप से पसीना बहाने की नसीहत दी गई। कुपोषण के खिलाफअभियान को तेज करते हुए कलेक्टर ने एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में लक्ष्य के अनुरूप बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से अजयगढ़ एनआरसी में महिला केयरटेकर रखने की व्यवस्था करने को कहा गया। टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा अब पूरी तरह यू-विन पोर्टल की एंट्री के आधार पर होगी, जिसके लिए सभी बीएमओ को अपने अधीनस्थ अमले को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने मातृ और शिशु मृत्यु के मामलों पर गहरी संवेदनशीलता जताते हुए कहा कि ऐसे बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए जिससे भविष्य में ऐसी हृदय विदारक घटनाएं न हों। क्षेत्र में फैली स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी बल दिया गया। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष हिदायत दी। उन्होंने जिले के समस्त अस्पतालों के वार्डों, ओपीडी और प्रतीक्षालयों में पर्याप्त कूलिंग व ठंडे पानी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही मैदानी अमले को निर्देशित किया गया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को लू (तापघात) से बचाव के प्रति जागरूक करें। बैठक में सीएमएचओ डॉ. आर.पी. तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. आलोक गुप्ता, डीपीओ अवधेश सिंह सहित सभी ब्लॉकों के बीएमओ और अंतरविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुड़ाई में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक अपने रिश्तेदारों के यहां पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जितेन्द्र सिंह यादव उम्र 22 वर्ष निवासी लुहेड़ी, जिला महोबा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह अपने रिश्तेदारों के यहां ग्राम कुदई में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। बताया जा रहा है कि नहाने के बाद जितेन्द्र अपने गीले कपड़े तार पर सुखा रहा था। इसी दौरान वह पास से गुजर रहे खुले बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना तेज था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही अजयगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि खुले बिजली के तार को लेकर कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। अचानक हुए इस हादसे से परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गई। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है।

कागजों में होता रहा जल संरक्षण, वक्त आया तो पानी हो गया गायब

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अप्रेल। जब पानी की मांग बढ़ती है तो पानी गायब हो जाता है, जब बिजली की मांग होती है तो बिजली, ये कैसी विडम्बना है कि गर्मी में जब पानी की आवश्यकता है तो पेयजल का संकट हो रहा है करोड़ों की योजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण भी काम नहीं आ रहा है। जल संरक्षण के सभी प्रयास विफल दिखाई दे रहे हैं।

नाम बदल बदल कर विगत लगभग तीन दशकों से जल संरक्षण मे लगभग अरबों रूपये फूंक डाले गये लेकिन सब विफल रहे क्योंकि कागजी खानापूर्ति एवं कमीशन खोरी के चलते सही कार्य नहीं हो सके। अब जल गंगा संवर्धन के नाम पर पर खानापूर्ति की जा रही है। आखिर योजनाओं के नाम पर कब तक जनता के साथ मजाक होता रहेगा। जल संरक्षण के नाम पर बहुत प्रयास हुये किन्तु उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आ पाये। उद्देश्य था कि घटते जल स्तर को बढ़ाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास किये जाय। इसलिये इसको लेकर योजनायें और परियोजनाओं को स्वीकृति भी मिली। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उनका क्रियान्वयन भी किया गया। किन्तु आज यदि देखा जाय तो पता चलता है कि जल स्तर नहीं बढ़ सका। जिसका परिणाम समय से पहले तेजी से घटते जल स्तर के रूप में सामने आ रहा है।

पुरानी जल संरचनायें भी विलुप्त:- पुरानी जल संरचनाओं को भी सुनियोजित साजिस के तहत नष्ट कर दिया। आज मनरेगा से कपिलधारा कूप के नाम पर कुओं का निर्माण करवाया जा रहा है। किन्तु इसके विपरीत कई पुराने कुयें व बावलियों को नष्ट कर दिया गया या नष्ट किया जा रहा है। जबकि ऐसी पुरानी संरचनाओ को पुनर्जीवित किया जा सकता था। इसी तरह से कई तालाबों को भी नष्ट कर दिया गया। वहां खेती शुरू हो गई। अथवा शहरी क्षेत्र में होने के कारण वहां कालोनियां का निर्माण हो गया, आबादी क्षेत्र बन गये, आवासीय कालोनियों का निर्माण हो गया। आज ऐसे क्षेत्रों में उन तालाबों के नाम पर मुहल्ले जरूर बस चुके हैं। इसी तरह से जो शेष बचे हुये हैं उनका भी अस्तित्व संकट में हैं। क्योंकि यहां पुनरूद्धार के नाम पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अन्यथा कई तालाबों को जिन्दा किया जा सकता है। यही हाल तालाब गहरीकरण का भी:- ग्रामीण विकास में एक समय पर तालाब गहरीकरण को काफी महत्व दिया जा रहा था। व्यापक पैमाने पर तालाब गहरीकरण के नाम पर काम स्वीकृत हुये। एक-एक तालाबों का कई बार गहरीकरण हुआ किन्तु यह सब एक घोटाले के रूप में ही प्रकाश में आया। भ्रष्टाचारियों ने मिलजुलकर करोड़ों का बजट साफकर दिया। पंचायतों ने भी उसमें हाथ साफ किया। अंतत: सरकारों ने जब देखा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो तालाब गहरीकरण योजना को बंद कर दिया गया। यदि नियमों में सुधार होता, कड़ी निगरानी होगी, गुणवत्ता पूर्ण करवाने में ध्यान दिया जाता तो शायद आज कई तालाब आज जीवित दिखाई देते और उसका असर जल स्तर पर भी होता किन्तु यहां तो दिशा निर्देश कुछ होते हैं। जबकि मौके पर कुछ और होता है। कागजों में उपलब्धियों का पहाड़ गढ़ दिया जाता है। समीक्षा होती है तो उसमें आंकड़ों के आधार पर पीठ ठोंकी जाती है। कार्यस्थल तक जाने के लिये सक्षम व वरिष्ठ अधिकारियों को फुर्सत ही नहीं होती। क्योंकि वहां तक जाने पर पूरा खेल विगड़ सकता है। जनता भी विरोध सामने आ सकती है। सरकारी भ्रमण के नाम जो पीओएल बचा लेते वह भी नुकसान में चला जाता। इसलिये सब कुछ जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय में ही बैठकर करने से फायदा होता है। यही कारण है कि आज जल संरक्षण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। जहां समस्या है वहां की जनता ही इसका खामियाजा भुगत रही है। इसलिये यह सवाल तो उठेंगे ही कि जल संरक्षण के नाम पर जो काम हुये उनका परिणाम आज तक क्यों दिखाई नहीं दिया? आखिर कब तक जनता समझ पायेगी कि प्रयोग सफल हुआ?

आंकड़ों में मिलेगा अभियान का डाटा

जल संरक्षण के नाम पर निर्मित होने वाली संरचनाओं का डाटा पता किया जाय तो पता चलेगा कि जब से इस विषय में चिन्ता हुई और प्रोजेक्ट शुरू हुये तब से आज तक व्यापक पैमाने पर संरचनाओं का निर्माण किया गया। पुराने अभिलेखो में ऐसे प्रमाण आज भी मिल सकते हैं। किन्तु उन संरचनाओं की आज यदि खोजबीन होगी एवं उनका भौतिक सत्यापन होगा तो दस फीसदी संरचनायें भी भौतिक रूप से नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में इसका जबाब कौन देगा कि निर्मित होने वाली संरचनायें यदि बनी तो वे कहां विलुप्त हो गई। आखिर कुछ न कुछ अंश तो दिखना चाहिये। कुछ न कुछ प्रमाण तो मिलना ही चाहिये। किन्तु यहां धरातल में कुछ भी नहीं मिल सकता।

जब आया संकट तब जुगाली

आज जब जल संकट गहराता जा रहा है तो इसको लेकर चिन्ता भी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां न तो नहरें हैं और न ही कोई बांध वहां यह समस्या और भी कठिन होती है। चूंकि ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल ही एक माध्यम होता है जिसके सहारे खेती भी होती है और उद्यानिकी से लेकर अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होता है आज वही स्थिति दिखाई दे रही है। आज यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने वर्षों से जल संरक्षण के नाम पर भारी भरकम राशि खर्च हुई, किन्तु उसका परिणाम क्या निकला। सकारात्मक परिणाम आखिर क्यों नहीं निकल पाया। जल स्तर क्यों नहीं बढ़ा। तकनीकी रूप से जो अध्ययन किये गये थे और जो दिशा निर्देश दिये गये थे उसी के अनुसार यदि योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ तो कुछ परिणाम तो दिखने चाहिये। किन्तु यहां तो स्थिति और भी भयावह ही दिखाई दे रही है।